

राष्ट्रीय शिक्षा नीति—ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा

डॉ. सत्येन्द्र सिंह¹, डॉ. कल्पना दीक्षित², शिवम् तिवारी²

¹ विभागाध्यक्ष, श्री रावतपुरा सरकार कॉलेज, आरी, झाँसी, उत्तर प्रदेश, भारत

² प्रवक्ता, श्री रावतपुरा सरकार कॉलेज, आरी, झाँसी, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश

जीवन में शिक्षा के महत्व को देखते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्तमान सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में व्यापक बदलावों के लिये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। करीब तीन दशक के बाद देश में नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई है। उम्मीद की जा रही है कि यह शिक्षा नीति शिक्षा क्षेत्र में नवीन और सर्वांगीण परिवर्तनों की आधारशिला रखेगी। शिक्षा तक सबकी आसान पहुँच, समता, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेही के आधारभूत स्तंभों पर निर्मित यह शिक्षा नीति सतत विकास के 'एजेंडा 2030' के अनुकूल है और इसका उद्देश्य 21वीं शताब्दी की आवश्यकताओं के अनुकूल विद्यालयीन और महाविद्यालयीन शिक्षा को अधिक समग्र, लचीला बनाते हुए भारत को एक ज्ञान आधारित जीवंत समाज और वैश्विक महाशक्ति में बदलकर प्रत्येक छात्र में निहित अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाना है।

मूल शब्द: शिक्षा नीति के प्रमुख सिद्धान्त, राष्ट्रीय एकीकरण की भावना, डिजिटल शिक्षा एवं उससे सार्वभौमिक विकास।

आज से 200 साल पहले किसी ने सोचा भी न होगा कि हम एक जगह बैठके किसी अन्य जगह में बैठे हुए व्यक्ति से अपने ही स्थान पर बैठके बात करेंगे। तब संचार के माध्यम केवल चिट्ठियाँ संदेश वाहक दूत ही होते थे। ग्राहम बेल ने टेलीफोन की खोज कर के इस अकल्पनीय प्रतीत होने वाली बात को संभव बनाया। मारकोनी ने रेडियो खोजा जिस समय हमें दूर के समाचार और मनोरंजन कार्यक्रमों को सुन पाना संभव हुआ। जॉन लॉगी बेयर्ड ने श्रव्य माध्यम से हमें दृश्य और श्रव्य माध्यम में प्रवेश कराया टेलीविजन बनाके। संचार माध्यम से लोगों की पहुंच आसान हुई। इसी क्रम में कंप्यूटर का आविष्कार हुआ कठिन गणनाएं आसान हुई। टेलीफोन का आकार छोटा हुआ और तार से बेतार संचार की ओर विश्व बढ़ा, साथ ही कंप्यूटर का आकार छोटा हुआ और वह केवल गणनाओं तक ही सीमित न बल्कि उसके नए आयाम देखने को मिले। वर्ल्डवाइड वेब की खोज ने संचार की दुनिया को चमत्कृत कर दिया। ये बात बहुत पुरानी नहीं केवल 30 वर्ष पहले की बात है, संचार की दुनिया में तेजी से बदलाव हुए, कंप्यूटर छोटे छोटे हाथों में आ गए और हम शायद ही किसी ने सुना हो हम घर बैठकर संमदर पार भी बात कर सकेंगे और संचार के इस क्षेत्र में बढ़ रहे हैं। इस संचार क्रांति ने बहुत सी असम्भव लगने वाली बातों को संभव बना दिया है। जीवन में शिक्षा अतिमहत्वपूर्ण था। यद्यपि प्राचीन ग्रन्थ रामायण में मयार्दापुरुषोत्तमराम के द्वारा पुष्पक विमान से अयोध्या पहुंचना तथा महाभारत के संजय के द्वारा युद्ध के समय हो रही घटनाओं का सजीव वर्णन पर इंगित करता है कि प्राचीन काल में हम तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी के रूप में काफी सक्षम थे। जब प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित होगा तभी वह अपने अधिकारों को जान पाएगा और उपयोग कर सकेगा। इससे जी से बदलती हुई दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चल पाएगा। इसके लिए सब से महत्वपूर्ण है सभी लोगों तक शिक्षा की सुलभ पहुंच।

वर्तमान परिस्थितियों में कोविड 19 महामारी के दौर ने जैसे सब कुछ थामसा दिया था लेकिन इससे भी लोगों ने लड़ना सीखा और लोग नए माध्यमों की ओर तेजी से बढ़े। इन सब में सब से महत्वपूर्ण शिक्षा का क्षेत्र रहा। सभी शैक्षणिक संस्थान बन्द होने से छात्रों की पढ़ाई पर जबरदस्त असर पड़ा। इसी दौर में भारत में पहले से ही चल रहे ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म जैसे अनएकेडमी और बायजू जैसे शिक्षा ऐप्स का प्रसार तेजी से बढ़ा।

साथ ही सरकारी शिक्षण संस्थानों ने इनसे कदम मिलाने में कोई कसर नहीं रखी। गूगलमीट, माइक्रो सॉफ्ट टीम आदि। द्वितरफा संवादीय माध्यमों से बच्चों को पढ़ाते रहे। साथ ही सरकार द्वारा जारी एजुकेशनल चैनल ने बच्चों की मदद की। नई परिस्थितियों और वास्तविकताओं में यह आपेक्षित है कि जब भी और जहां भी शिक्षा के पारम्परिक और विशेष साधन संभव न हो वहां हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए वैकल्पिक साधनों के साथ तैयार हो। इस सम्बंध में, नई शिक्षा नीति 2020 में प्रौद्योगिकी की संभावित चुनौतियों को स्वीकार करते हुए उससे मिलने वाले लाभों के महत्व पर भी ध्यान केंद्रित है। साथ ही सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने से संबंधित वर्तमान एवं भावी चुनौतियों का सामना करने के लिए मौजूदा डिजिटल प्लेटफॉर्म और क्रियान्वित आईसीटी आधारित पहलों को अनुकूल और विस्तारित करना होगा। डिजिटल प्रौद्योगिकी के उद्भव और स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक सभी स्तरों पर शिक्षण के लिए प्रौद्योगिकी के उभरते हुए महत्व को देखते हुए नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति –2020 में डिजिटल शिक्षा में बदलाव हेतु निम्न प्रयासों को शामिल किया गया है –

ऑनलाइन शिक्षा की हानियों को कम करते हुए उसे शिक्षा के साथ एकीकृत करने के लाभों का मूल्यांकन करने के लिए और छात्रों को उपकरणों कि आदत, ई-कंटेंट का सबसे अच्छा प्रारूप आदि जैसे संबंधित विषयोंका अध्ययन के लिए एनसीटीई, एनआईओएस, इग्नू, आईआईटी, एनआईटी आदि जैसी उपयुक्त एजेंसियों की पहचान की जाएगी। भारत के क्षेत्रफल, विविधता, जटिलता और डिवाइस अर्थ बोध को हल करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में खुले, परस्पर विकसित सार्वजनिक डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करने की आवश्यकता है जिसका उपयोग कई प्लेटफॉर्मों और प्वाइंट सॉल्यूशंस द्वारा किया जा सकता है। साथ ही इनमें लगातार विकास किया जाएगा ताकि तेजी से बदलती हुई तकनीकी के साथ आगे बढ़ा जा सके। शिक्षार्थियों की प्रगति की निगरानी के लिए शिक्षकों को सहायक उपकरण के एक संरचित, उपयोगकर्ता अनुकूल, विकसित सेट प्रदान करने के लिए स्टडी वेब्स आफ एक्टिव लर्निंग फार यंग इन्सपायरिंग माइंड्स (स्वयम), डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर फार नालेज शेयरिंग (दीक्षा) जैसे उपयुक्त मौजूदा ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म का विस्तार किया जाएगा। वर्तमान महामारी ने स्पष्ट कर दिया है कि ऑनलाइन कक्षाओं के

आयोजन के लिए दो-तरफा वीडियो और दो तरफा-ऑडियो इंटरफेस जैसे उपकरण एक वास्तविक आवश्यकता है।

कोर्स वर्क, लर्निंग गेम्स और सिमुलेशन, ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी के निर्माण सहित कंटेंट की एक डिजिटल रिपोजिटरी विकसित की जाएगी, जिसमें प्रभावशीलता और गुणवत्ता के लिए उपयोगकर्ताओं द्वारा रेटिंग करने के लिए एक स्पष्ट सार्वजनिक प्रणाली होगी। छात्रों के लिए मनोरंजन आधारित अधिगम हेतु उपयुक्त उपकरण जैसे ऐप, स्पष्ट संचालन निर्देश के साथ कई भाषाओं में भारतीय कला और संस्कृति का एकीकरण आदि भी बनाए जाएंगे। छात्रों को ई-सामग्री का प्रसार करने के लिए एक विश्वसनीय बैकअप तंत्र प्रदान किया जाएगा।

जैसा कि विदित है कि अभी भी डिजिटल माध्यमों का देश के सभी स्रोतों में पहुंचना कठिन है। जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है, जिसकी डिजिटल पहुंच अत्यधिक सीमित है, मौजूदा जनसंचार माध्यम जैसे टेलीविजन, रेडियो और सामुदायिक रेडियो का उपयोग टेलीकास्ट और प्रसारण के लिए बड़े पैमाने पर किया जाएगा। सभी भारतीय भाषाओं में सामग्री पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और इस पर विशेष बल दिया जाएगा कि जहाँ तक संभव हो, शिक्षकों और छात्रों तक डिजिटल सामग्री उनकी सीखने की भाषा में पहुंचे।

शैक्षणिक सामग्री का संभव सभी भाषाओं में उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा सकेगा। दीक्षा, स्वयं और स्वयंमप्रभा जैसे मौजूदा ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाएगा ताकि सभी छात्रों को गुणवत्ता पूर्ण व्यावहारिक और प्रयोग आधारित अनुभव का समान अवसर प्राप्त हो। छात्रों और शिक्षकों को पहले से लोड की गई सामग्री वाले टैबलेट जैसे उपयुक्त डिजिटल उपकरण पर्याप्त रूप से देने की संभावना पर विचार किया जाएगा और उन्हें विकसित किया जाएगा।

शिक्षकों को शिक्षार्थी केंद्रित अध्यापन में यह गहन प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा उन्हें इस हेतु प्रेरित किया जायेगा और यह भी बताया जाएगा कि वे ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्मों और उपकरणों का उपयोग करके उच्चतर गुणवत्ता वाली ऑनलाइन सामग्री का स्वयं निर्माण कर ई-सामग्री के साथ साथ छात्रों में आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए शिक्षक की भूमिका पर जोर दिया जाएगा।

प्रस्तावित राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र अथवा समग्र विकास के लिए प्रदर्शन, आकलन, समीक्षा और विश्लेषण कर स्कूल बोर्ड, एनटीए और अन्य चिह्नित निकाय मूल्यांकन रूपरेखाओं का निर्धारण करेंगे और कार्यान्वित करेंगे, जिसमें दक्षताओं, पोर्टफोलियो, रुब्रिक्स, मानकीकृत मूल्यांकन और मूल्यांकन विश्लेषण के डिजाइन शामिल होंगे। 21 वीं सदी के कौशल पर ध्यान केंद्रित करते हुए शिक्षा प्रौद्योगिकियों का उपयोग कर मूल्यांकन के नए तरीकों का अध्ययन किया जाएगा।

डिजिटल शिक्षा व शिक्षण को बढ़ावा देने के साथ ही, परंपरागत व्यक्तिगत रूप से आमने-सामने सीखने के महत्व को भी पूरी तरह से स्वीकार किया जाता है। तदनुसार, विभिन्न विषयों के लिए सीखने के विभिन्न मिश्रित प्रभावी मॉडल, उपयुक्त प्रतिकृति के लिए चिह्नित किए जाएंगे।

जैसे जैसे ऑनलाइन/डिजिटल शिक्षा पर शोध सामने आ रहे हैं, उपयुक्त निकाय ऑनलाइन डिजिटल शिक्षण-शिक्षण के लिए सामग्री, प्रौद्योगिकी और शिक्षाशास्त्र के मानक स्थापित करेंगे। ये मानक राज्यों, बोर्डों, स्कूलों और स्कूल परिसरों, उच्चतर शिक्षण संस्थानों, आदि द्वारा ई-लर्निंग के लिए दिशानिर्देश तैयार करने में मदद करेंगे। सरकार ने ऑनलाइन डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु निम्न शिक्षण के मानक तैयार करने हेतु राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी फोरम ने लगभग 3.1 लाख सरकारी स्कूलों, जिनके पास सूचना व संचार तकनीक सुविधाएँ नहीं हैं, को ऐसी

सुविधाओं से लैस करने के लिये केंद्र सरकार 55,840 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित करेगी। MHRD ने आगामी पाँच वर्षों में डिजिटल पाठ्यक्रम सामग्री और संसाधनों के विकास एवं अनुवाद पर 2,306 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव किया है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2026 तक देश भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले लगभग 4.06 करोड़ छात्रों (देश की कुल छात्र संख्या का लगभग 40 प्रतिशत) को लैपटॉप और टैबलेट प्रदान करने की भी योजना बनाई है तथा इस कार्य के लिये कुल 60,900 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है।

प्रभावशाली ऑनलाइन प्रशिक्षक बनने के लिए शिक्षकों को उपयुक्त प्रशिक्षण और विकास चाहिए। पहले से ही यह माना नहीं जा सकता कि पारंपरिक कक्षा में एक अच्छा शिक्षक स्वचालित रूप से चलने वाली एक ऑनलाइन कक्षा में भी एक अच्छा शिक्षक सिद्ध होगा। अध्यापन में आवश्यक परिवर्तनों के अलावा, ऑनलाइन आकलन के लिए भी एक अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। बड़े पैमाने पर ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने में कई चुनौतियाँ हैं, जिनमें ऑनलाइन परिवेश में पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रकार से संबंधित सीमाएँ, नेटवर्क और बिजली के व्यवधान से जूझना और अनैतिक प्रथाओं को रोकना शामिल हैं। कुछ प्रकार के पाठ्यक्रम विषय, जैसे प्रदर्शन कला और विज्ञान व्यावहारिक ऑनलाइन। डिजिटल शिक्षा क्षेत्र में सीमाएँ हैं, जिन्हें नवीन उपायों के साथ कुछ सीमा तक दूर किया जा सकता है इसके अलावा, जब तक ऑनलाइन शिक्षा को अनुभवात्मक और गतिविधि-आधारित शिक्षा के साथ मिश्रित नहीं किया जाता, तब तक यह सीखने के सामाजिक, भावात्मक और साइकोमोटर आयामों पर सीमित फोकस वाली एक स्क्रीन-आधारित शिक्षा मात्र ही बन जाएगी।

ऑनलाइन/डिजिटल शिक्षा का लाभ तब तक नहीं उठाया जा सकता जब तक डिजिटल इंडिया अभियान और किफायती कंप्यूटिंग उपकरणों की उपलब्धता जैसे ठोस प्रयासों के माध्यम से डिजिटल अंतर को समाप्त नहीं किया जाता। यह जरूरी है कि ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग समानता के सरोकारों को पर्याप्त रूप से संबोधित किया जाए।

ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर दिए जाने के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह भी कहा गया है कि ऑनलाइन एजुकेशन का हम पूरी तरह फायदा तब तक नहीं उठा सकते, जब तक देश में डिजिटल डिवाइड है। डिजिटल डिवाइड से सीधा मतलब है अधिकतर लोगों के पास ऑनलाइन एजुकेशन के लिए संसाधन उपलब्ध न होना। वर्तमान समय में भी भारत में डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है, देश में अब भी उन छात्रों की संख्या काफी सीमित है, जिनके पास लैपटॉप या टैबलेट कंप्यूटर जैसी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। अतः ऐसे छात्रों के लिये ऑनलाइन कक्षाओं से जुड़ना एक बड़ी समस्या है। शिक्षकों के लिये भी तकनीक एक बड़ी समस्या है, देश के अधिकांश शिक्षक तकनीकी रूप से इतने प्रशिक्षित नहीं हैं कि औसतन 30 बच्चों की एक ऑनलाइन कक्षा आयोजित कर सकें और उन्हें ऑनलाइन ही अध्ययन सामग्री उपलब्ध करा सकें। इंटरनेट पर कई विशेष पाठ्यक्रमों या क्षेत्रीय भाषाओं से जुड़ी अध्ययन सामग्री की कमी होने से छात्रों को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कई विषयों में छात्रों को व्यावहारिक शिक्षा की आवश्यकता होती है, अतः दूरस्थ माध्यम से ऐसे विषयों को सिखाना काफी मुश्किल होता है ऐसे विषय जो प्रायोगिक हों।

भारत सूचना एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विश्व के अग्रणी देशों में ही डिजिटल इंडिया अभियान से पूरे देश में सशक्त समाज एवं सम्बन्धित अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन आ रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है कि विश्व स्तरीय डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर, शैक्षिक डिजिटल कंटेंट सामग्री और क्षमता का

निर्माण करने के लिए एक समर्पित इकाई का निर्माण किया जायेगा। इसके अन्तर्गत प्रशासन, शिक्षा, शैक्षिक प्रौद्योगिकी, डिजिटल शिक्षाशास्त्र और मूल्यांकन, ई-गवर्नेंस आदि के क्षेत्र से जुड़े निवेश हो तो जो समय-समय पर आवश्यकतानुसार अपने सुझाव देंगे।

बदलते वैश्विक परिदृश्य ने आनलाइन और डिजिटल शिक्षा, शिक्षण, अनिवार्य होते जा रहे हैं शिक्षा गुणात्मक शिक्षा एवं शोध हेतु आफलाइन और आनलाइन शिक्षा के मिश्रित स्वरूप निश्चित रूप से आने वाले वर्षों में प्रभावी भूमिका निभयेंगे। आन लाइन शिक्षा को और सशक्त बनाने हेतु देश के निजी क्षेत्र के उद्योगपतियों की भी सेवाएं अपेक्षित हैं। निश्चित रूप से इसमें अपनी उपयोगिता से शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आना संभव है। समयानुकूल परिवर्तनों के साथ साथ शिक्षा को भारत विश्व के शीर्षस्थ स्थान पर स्थापित करने का प्रयास समाज को करना होगा। तभी हम इस क्षेत्र के विश्व का नेतृत्व करने में सफल होंगे।

संदर्भ स्रोत

1. आस्थाना, विपिन श्रीवास्तव, शैक्षिक अनुसंधान एवं सांख्यिकी, अग्रवाल विजय एवं आस्थाना, निधि पब्लिकेशन आगरा (2012)।
2. गुप्ता एस.सी. एवं कपूर व्ही.के.:फण्डामेन्टल ऑफ मैथमेटिकल स्टेटिस्टिक्स, सुल्तान चंद एण्ड संस (1992 संस्करण) 23 दरियागंज नई दिल्ली।
3. भटनागर, आर.पी. (1986) 'शैक्षिक अनुसंधान' मेरठ रायल बुक डिपो, मेरठ।
4. पाण्डेय, रामसकल (1989), 'शिक्षा दर्शन' विनोद पुस्तक मंदिर आगरा-2।
5. पाठक, पी.डी. (1986) 'शिक्षा मनोविज्ञान' विनोद पुस्तक मंदिर डॉ. रागेय राघव मार्ग आगरा-2।
6. माथुर, एस.एस. 'शिक्षा के दार्शनिक तथा सामाजिक आधार'।
7. स्वरूप, एन.आर. (1996):शिक्षा सिद्धांत, लॉयन बुक डिपो मेरठ।
8. समर्थ, शिक्षक उन्मुखी कार्यशाला, विवेकानंद केन्द्र कन्याकुमारी मध्य प्रान्त एफ 49/1, दक्षिण तात्या टोपे नगर, भोपाल।
9. शर्मा, आर.ए. (1987) 'शिक्षा अनुसंधान' आर. लाल बुक डिपो, मेरठ।
10. श्रीवास्तव के. एम. (1995) :शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन, विश्वविद्यालय बुक डिपो रीवा।
11. डॉ. आन.एन. तिवारी (2021) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जी.एच. पब्लिकेशन, इलाहाबाद।